जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते है तब आप अपने लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खोलते है।
– अज्ञात

कच्चे तेल की कीमत माइनस में

लोग घरों में बंद हैं। गाड़ियां नहीं चल रहीं, विमान नहीं उड़ रहे, कारखानों में भी उत्पादन ठप है। इसके कारण क्रूड की मांग में भारी गिरावट आई है। सऊदी अरब और रूस के बीच चले प्राइस वॉर ने पहले ही तेल का अपच कर रखा था।

रमन शर्मा।

कोरोना संकट की गहरी मार कच्चे तेल के वैश्विक बाजार पर भी पड़ी है। वायदा बाजार में सोमवार को इसकी कीमतें इतिहास में पहली बार शून्य से भी नीचे पहुंच गईं। अमेरिकी वायदा बाजार में कच्चा तेल लुढ़कते हुए नेगेटिव में चला गया, शून्य से 36 डॉलर नीचे। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का वायदा भाव मई डिलीवरी के लिए –37.63 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

कच्चे तेल की कीमत माइनस में जाने का यह मतलब नहीं है कि आज या कल से तेल खरीदने पर इसे बेचने वाला आपको साथ में कुछ पैसे भी देगा। दरअसल मई महीने में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए जो ठेके दिए जाते हैं वे अब नेगेटिव में चले गए हैं। तेल उत्पादक देश दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदने को कह रहे हैं, लेकिन वैश्विक लॉकडाउन के कारण कोई भी देश तेल नहीं खरीद रहा, इसलिए कीमत इतनी गिर गई। हालत यहां तक पहुंच गई है कि तेल उत्पादक देश अब खरीदारों को पैसे देकर तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो उनके सामने स्टोरेज की समस्या खड़ी हो जाएगी।

असल में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन है। लोग घरों में बंद हैं। गाड़ियां नहीं चल रहीं, विमान नहीं उड़ रहे, कारखानों में भी उत्पादन ठप है। इसके कारण क्रूड की मांग में भारी गिरावट आई है। सऊदी अरब और रूस के बीच चले प्राइस वॉर ने पहले ही तेल का अपच कर रखा था। अब तेल उत्पादक देशों के सामने तेल रखने की विकराल समस्या खड़ी हो रही है, जिसे देखते हुए कई तेल फर्में विशाल टैंकर शिप किराये पर ले रही हैं ताकि अतिरिक्त स्टॉक उनमें रखा जा सके। अमेरिका के लिए यह सिरदर्द सबसे बड़ा है क्योंकि उसकी शेल ऑयल कंपनियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे इन हालात से कैसे निपटें। ऐसी कई कंपनियां अगले कुछ महीनों में दिवालिया हो सकती हैं, जिससे वहां बेरोजगारी का संकट भी गहराएगा।

कच्चे तेल की कीमतों के रसातल में पहुंचने का भारत पर भी बुरा असर पड़ेगा। दरअसल इसके चलते कई खाड़ी देशों की इकोनॉमी डावांडोल हो सकती है क्योंकि उनका ज्यादातर जीडीपी तेल से ही आता है। इन देशों में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं जो हर साल करीब 50 अरब डॉलर की रकम भारत भेजते हैं। खाड़ी की इकोनॉमी के गड़बड़ होने का मतलब है, इनमें से अधिकतर का बेरोजगार हो जाना। इसके अलावा भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है, जिस पर जबर्दस्त आफत आने वाली है। संकट से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक नई मुश्किल होगी लेकिन अभी इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। हमें धैर्यपूर्वक स्थितियों के संभलने का इंतजार करना होगा और खाड़ी देशों से अपना संवाद बनाए रखना होगा।

परिमाण

अशोक वोहरा।

प्रकृति की अद्भुत घटनाएं जीवन के निश्चित क्रम में शिक्षा देने के लिए आती हैं, यद्यपि ये जिस समय होता है उसी के साथ उनकी अनिश्चितता के परिमाण भी प्रकट होते हैं। यह तभी होने को तत्पर होते हैं जब प्रकृति के साथ अनावश्यक रुप से छेड़छाड़ की जाती है।

सप्ताह नियतकालिक है लेकिन यह प्राकृतिक समयावधि न होकर मानव निर्मित है, इसीलिए पांच या छः दिन के अंतराल पर हम एक या दो दिन अपने आराम व व्यक्तिगत कार्यों के लिए ले सकेंगे। समयावधि में निरंतरता चाहें वो प्राकृतिक हो या अन्य एक खाका तय करती है और इससे जीवन व्यवस्थित होकर तार्किक रुप से निर्धारित हो सकेगा।यह चाहें तो अव्यवस्थित हो सकता है। लेकिन जब अव्यवस्था का कोलाहल एक बार चरम बिंदु पर पहुँच जाता है, तो तंत्र स्वंय को पहचानता है और समस्त क्रम का पुर्निमाण करता है।

संपादकीय

संक्रमण का दायरा

देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाक डाउन लागू करने की घोषणा की तो अधिकांश आबादी की जिन्दगी घर की चहार दीवारी के भीतर सिमट कर रह गई और जब देश के विभिन्न राज्यों में इस वायरस के संक्रमण का दायरा बढने लगा तो यह जानने के लिए लोगों की अधीरता भी बढने लगी कि देश के किस राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की क्या स्थिति है। लोगों की यह अधीरता अभी भी बरकरार है बल्कि अगर यह कहें कि कोरोना को लेकर देश दुनिया के हालात जानने की यह उत्सुकता पहले से भी अधिक बढ़ गई है तो गलत नहीं होगा द्यहमारी इस उत्सुकता को शांत करने मे इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया, दोनों ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुबह शाम अगर हमें अगर दैनिक समाचार पत्रों की अधीरता से प्रतीक्षा करते हैं तो दिन मेंअधिकांश समय या तो हम दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं अथवा मोबाइल के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बारे में नवीनतम जानकारी हासिल करके अपनी उत्सुकता को शांत करने का प्रयास करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में नवीनतम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जिस समर्पण भावना के साथ रात दिन अपने काम में जुटे हुए है उसके लिए वे निसंदेह समाज से सराहना पाने के हकदार हैं। ये लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से पूरे साहस के साथ जूझते हुए अपने काम में कुछ इस तरह जुटे रहते हैं कि उस समय बाकी सुख सुविधाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखतीं। चूंकि हम मीडिया के लोगों के सीधे संपर्क में नहीं रहते इसलिए हम उनकी कठिनाईयों से अवगत नहीं हो पाते।

जरूरत पूरी करने के लिए डीआरडीओ से लेकर भारतीय सेना के बेस वर्कशॉप और भारतीय नौसेना के डॉकयार्ड तक सब जगह आविष्कार हो रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में 'हथियार' देसी इस्तेमाल हो रहे हैं।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा

पूनम पांडे

कोरोना से उपजा यह विशिष्ट दौर अपने ढंग से हमें यह संदेश भी दे रहा है कि कोई भी जंग आयात किए गए हथियारों के ही सहारे नहीं जीती जा सकती। खुद को मजबूत करना है तो हथियार भी खुद के ही तैयार करने होंगे विदेश से आए एक वायरस ने जहां सबकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है, वहीं भारत की ताकत को भी परखने का मौका दिया है। जरूरत पूरी करने के लिए डीआरडीओ से लेकर भारतीय सेना के बेस वर्कशॉप और भारतीय नौसेना के डॉकयार्ड तक सब जगह आविष्कार हो रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में 'हथियार' देसी इस्तेमाल हो रहे हैं। कहीं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विमेंट (पीपीई) बन रहा है तो कहीं यूवी सैनिटाइजेशन डिवाइस।

यह विशिष्ट दौर अपने ढंग से हमें यह संदेश भी दे रहा है कि कोई भी जंग आयात किए गए हथियारों के ही सहारे नहीं लडी और जीती जा सकती। खुद को मजबूत करना है तो हथियार भी खुद के ही तैयार करने होंगे। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। रक्षा क्षेत्र में भी इस नीति को अपनाने की बात हुई है, लेकिन सचाई यही है कि अभी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर हम चंद

कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

अभी भारतीय सेना बड़ी संख्या में एम्युनिशन (गोला–बारूद) स्टोर कर रखती है। आयातित हथियारों में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद भी अमूमन आयात ही किया जाता है। हर एम्युनिशन की एक लाइफ होती है जिसके बाद वह खराब होने लगता है। ऐसे में यह बर्बाद ही होता है। इनको स्टोर करना भी खर्चीला होता है। स्टोरेज डिपो की हर वक्त की पहरेदारी भी बजट बढ़ा देती है। अभी सेना 40 दिन का एम्युनिशन स्टोर करती है। यानी अगर युद्ध के हालात बन जाए तो कम से कम 40 दिन तक लगातार लड़ाई लड़ने के लिए एम्युनिशन पूरा होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ इस पर एकमत हैं कि पाकिस्तान 14–15 दिन से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं रखता क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। अगर चीन की तरफ से कभी युद्ध की नौबत आई तो सब जगह लड़ाई एक साथ नहीं होगी। विचार किया जा सकता है कि क्या बड़ी मात्रा में स्टोर करने की बजाय ये भंडार कुछ कम किया जा सकता है। दूसरी बात कि मेक इन इंडिया के तहत अगर हथियार और गोला–बारूद भारत में ही बनने लगे तो फिर ज्यादा स्टोर करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी।

केंद्र सरकार ने कुछ वक्त पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद बनाया है। सीडीएस का दायित्व तीनों सेनाओं में समन्वय को बढ़ावा देने के साथ ही यह देखना भी है कि किस तरह बजट का सही इस्तेमाल हो। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की राह किस तरह आसान होती है यह भी सीडीएस के सामने एक अहम चुनौती है। मेक इन इंडिया का मतलब यह नहीं है कि सेनाओं की ताकत के साथ किसी तरह का समझौता हो। उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता से समझौता किए बगैर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं को भी दिलचस्पी दिखानी होगी। हालांकि तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से अलग–अलग मौकों पर मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है।

अष्टयोग-5032

7		4			3	
1	34		28	2	29	6
	5	2	6		1	7
2	31	6	33	4	28	
		1			2	
6	33	3	33	6	34	
		7	4			5

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5031 का हल

5	6	1	4	7	2	3
1	29	5	30	2	31	6
4	5	2	6	3	1	7
2	36	6	31	4	26	1
7	6	4	1	5	3	2
6	38	3	31	6	32	4
3	2	7	4	1	6	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

मॉर्डनाइजेशन की चुनौती

मोहन। एक कार्यक्रम में एयरफोर्स चीफ आरके भदौरिया ने उम्मीद जताई कि रक्षा क्षेत्र में भारतीयकरण तेजी से होगा और जब अगली बार दुश्मन से हवाई झड़प होगी तो हम भारतीय मिसाइल और वेपन सिस्टम से उसका जवाब दे सकेंगे। सेना के लिए बजट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि बजट का सही मैनेजमेंट हो। सीडीएस के सामने इसी बजट में सेना के मॉर्डनाइजेशन की चुनौती है। जितना ज्यादा स्वदेशीकरण होगा उतनी कीमत कम होगी और आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा बजट उपलब्ध हो सकेगा। भारत में इंडस्ट्री भी सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए हथियार, एम्युनिशन, इक्विमेंट बनाने के लिए आगे आ रही है, लेकिन इन्हें सरकार के सपोर्ट के साथ ही सेना से भी प्रोत्साहन की जरूरत है। सीडीएस भी कई बार मेक इन इंडिया के सहारे बजट कम करने की बात कह चुके हैं, लेकिन वह सेना के लिए इस राह को कैसे आसान और सुरक्षित बनाते हैं इस पर सबकी नजरें रहेंगी।